

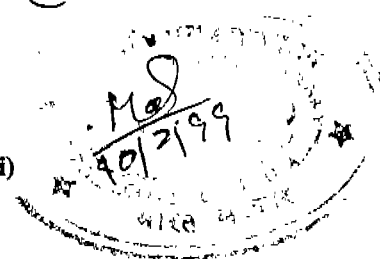


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 690]
No. 690]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 22, 1998/आश्विन 30, 1920
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 22, 1998/ASVINA 30, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 1998

आय-कर

का. आ. 917 (अ).—केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्,—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (बीसवाँ संशोधन) नियम, 1998 है ;
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. आयकर नियम, 1962 के नियम 45 में,—
(क) शीर्षक में "उप-आयुक्त (अपील) और" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा;
(ख) उपनियम (1) में "यथास्थिति उप-आयुक्त (अपील) या" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।
3. आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट II में,—
(क) प्ररूप सं. 35 में,—
(I) प्रारम्भिक भाग में,—
(अ) "आयकर उप-आयुक्त (अपील) और" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।
(आ) "उप-आयुक्त (अपील)" शब्दों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा।
(II) "उप-आयुक्त (अपील) या" शब्दों और कोष्ठकों का दोनों स्थानों पर, जहां-जहां वे आते हैं लोप किया जाएगा।
(III) अंत में आने वाले टिप्पण के अधीन टिप्पण 7 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे; अर्थात्,—
"8. अपील-ज्ञापन के साथ निम्नलिखित फीस होगी,—
(क) जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा संगणित निर्धारिती की कुल आय की दशा में, जिसके संबंध में अपील की जा रही है एक लाख रुपए या उससे कम है, वहां दो सौ पचास रुपए;

- (ख) जहां यथा पूर्वोक्त संगणित निर्धारिती की कुल आय की दशा में, जिसके संबंध में अपील की जा रही है, एक लाख रुपए से अधिक किन्तु दो लाख रुपए से अधिक नहीं है, वहां पांच सौ रुपए;
- (ग) जहां पूर्वोक्त यथा संगणित निर्धारिती की कुल आय की दशा में, जिसके संबंध में अपील की जा रही है दो लाख रुपए से अधिक है, वहां एक हजार रुपए।

9. फीस, निर्धारण अधिकारी से चालान अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में जमा की जानी चाहिए और आयकर आयुक्त (अपील) को चालान की एक प्रति भेजी जानी चाहिए।”;

(ख) प्ररूप सं. 36 में,—

- (i) मद 6 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्,—
 “6. 1 अक्टूबर, 1998 से पूर्व पारित आदेशों की बाबत ठप-आयुक्त (अपील)/धारा 154/250/271/271क/272क के अधीन आदेश पारित करने वाला आयुक्त (अपील)।”;
- (ii) मद 7 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्,—
 “1 अक्टूबर, 1998 से पूर्व पारित आदेशों की बाबत ठप-आयुक्त या ठप-निदेशक या धारा 154/272क/274(2) के अधीन आदेश पारित करने वाला संयुक्त आयुक्त या संयुक्त निदेशक।”;
- (iii) अंत में आने वाले टिप्पण के अधीन टिप्पण 2 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्,—
 “आयकर अधिनियम की धारा 253(1) के अधीन किसी निर्धारिती द्वारा अपील के ज्ञापन के साथ नीचे विनिर्दिष्ट फीस होगी :—
- (क) जहां निर्धारण अधिकारी द्वारा यथा संगणित निर्धारिती की कुल आय की दशा में, जिसके संबंध में अपील की जा रही है एक लाख रुपए या उससे कम है वहां पांच सौ रुपए;
- (ख) जहां यथा पूर्वोक्त संगणित निर्धारिती की आय की दशा में, जिसके संबंध में अपील की जा रही है एक लाख रुपए से अधिक किन्तु दो लाख रुपए से अधिक नहीं है वहां एक हजार पांच सौ रुपए;
- (ग) जहां यथा पूर्वोक्त संगणित निर्धारिती की कुल आय की दशा में, जिसके संबंध में अपील की जा रही है दो लाख रुपए से अधिक है वहां दस हजार रुपए की अधिकतम सीमा तक निर्धारित आय का 7%;
- (घ) प्रत्याक्षेप ज्ञापन की दशा में कोई फीस संदेय नहीं होगी;
- (ङ) मांग रोकने के लिए आवेदन के साथ पांच सौ रुपए की फीस होगी।

यह सुझाव दिया जाता है कि फीस, चालान अभिप्राप्त करने के पश्चात् प्राधिकृत बैंक की किसी शाखा या भारतीय स्टेट बैंक की किसी शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक की किसी शाखा में जमा की जानी चाहिए और अपील प्राधिकरण को अपील-ज्ञापन के साथ चालान की तीसरी प्रति भेजी जानी चाहिए। अपील प्राधिकरण बैंक, ड्राफ्ट, हुण्डी या अन्य पराक्राम्य लिखित स्वीकार नहीं करेगा।”।

[अधिसूचना सं. 10730/फा.सं. 142/53/98—टीपीएल]

डी. करुणाकर राव, अवर सचिव

पाद टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) दिनांक 26-3-1962 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे, और अन्तिम बार अधिसूचना सं. का.आ. 902 (अ) तारीख 13-10-1998 द्वारा संशोधित किए गए।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Central Board of Direct Taxes)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 1998

INCOME-TAX

S.O. 917(E).—In exercise of the powers conferred by section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely,—

1. (1) These rules may be called the Income-tax (20th Amendment) Rules, 1998;
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 45,—
 - (a) in the heading, the words and brackets “Deputy Commissioner (Appeals) and” shall be omitted;
 - (b) in sub-rule (1), the words and brackets “the Deputy Commissioner (Appeals) or as the case may be,” shall be omitted.

3. In Appendix II to the Income-tax Rules, 1962,—

(a) in Form No. 35,—

(i) in the opening portion,—

(A) the words and brackets “Deputy Commissioner (Appeals) of Income-tax and” shall be omitted.

(B) the words and the brackets “Deputy Commissioner (Appeals)” shall be omitted.

(ii) the words and the brackets “Deputy Commissioner (Appeals) or” at both the places where they occur, shall be omitted.

(iii) under the Notes, occurring at the end, after note 7, the following notes shall be inserted, namely,—

“8. The memorandum of appeal shall be accompanied by a fee of,—

- (a) where the total income of the assessee as computed by the Assessing Officer in the case to which the appeal relates is one hundred thousand rupees or less, two hundred fifty rupees;
- (b) where the total income of the assessee, computed as aforesaid to which the appeal relates is more than one hundred thousand rupees but not more than two hundred thousand rupees, five hundred rupees;
- (c) where the total income of the assessee, computed as aforesaid, in the case to which the appeal relates is more than two hundred thousand rupees, one thousand rupees.

9. The fee should be credited in a branch of the authorised bank or a branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India after obtaining a challan from the Assessing Officer and a copy of challan sent to the Commissioner of Income-tax (Appeals).”;

(b) in Form No. 36,—

(i) for item 6 and entries relating thereto, the following item and entries shall be substituted, namely,—

“6. The Deputy Commissioner (Appeals) in respect of orders passed before the 1st day of October, 1998/ Commissioner (Appeals) passing the order under section 154/250/271/271A/272A.”;

(ii) for item 7 and the entries relating thereto, the following item and the entries shall be substituted, namely,—

“The Deputy Commissioner or the Deputy Director in respect of orders passed before the 1st day of October, 1998 or the Joint Commissioner or the Joint Director passing the order under section 154/272A/274(2).”;

(iii) under the Notes occurring at the end, for note 2, the following shall be substituted, namely,—

“2. The memorandum of appeal by an assessee under section 253(1) of the Income-tax must be accompanied by a fee specified below :—

(a) where the total income of the assessee as computed by the Assessing Officer, in the case to which the appeal relates, is one hundred thousand rupees or less, five hundred rupees;

(b) where the total income of the assessee, computed as aforesaid, in the case to which the appeal relates is more than one hundred thousand rupees but not more than two hundred thousand rupees, one thousand five hundred rupees;

(c) where the total income of the assessee, computed as aforesaid, in the case to which the appeal relates is more than two hundred thousand rupees, one per cent. of the assessed income, subject to a maximum of ten thousand rupees;

(d) no fee shall be payable in the case of a memorandum of cross-objections;

(e) an application for stay of demand shall be accompanied by a fee of five hundred rupees.

It is suggested that the fee should be credited in a branch of the authorised bank or a branch of the State Bank of India or a branch of the Reserve Bank of India after obtaining a challan and the triplicate challan sent to the Appellate Tribunal with a memorandum of appeal. The Appellate Tribunal will not accept cheques, drafts, hundies or other negotiable instruments.”.

[Notification No. 10730/F. No. 142/53/98-TPL]

D. KARUNAKARA RAO, Under Secy.

Note : The Principal rules were published vide notification No. S.O. 969(E) dated 26-3-1962 and were last amended vide notification No. S.O. 902(E) dated 13-10-1998.

